245 अमरीकी डालर प्रति टन एफ० ओ०वी० पर किया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 1986 से प्रचलित यूरिया के मूल्य को जुलाई, 1991 में 2350 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रतिटन किया गया। अगस्त, 1991 में इसे घटा कर 3060 रुपये प्रति टन कर दिया गया। 1994 में मूल्य में वृद्धि 1991 में प्रचलित मूल्य पर केवल प्रतिशत तक है।

फास्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों के मूल्यों में उनके विनियंत्रण के कारण उर्वरक लागत सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर अगस्त, 1992 में वृद्धि की गई।

(ङ) से (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरक पोषकों की खपत नीचे दी गई है:—

पोषक	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (संभावित)
एन	80.46	84.27	87.89	98.00
पी	33.21	28.44	26.69	33.26
के	13.61	8.84	9.08	12.61
योग	127.28	121.55	133.66	143.87

देश में फास्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार एम०पी०ओ०, स्वदेशी डी०ए०पी० पर 1000 रुपये प्रति टन, स्वदेशी मिश्रणों पर अनुपातिक प्रति टन रियायत और स्वदेशी सिंगल सुपर फास्फेट (एस०एस०पी०) पर 340 रुपये प्रति टन की छूट दे रही है।

राष्ट्रीय बीज निगम को हुये घाटे

4067. **श्री एस०एस० सुरजेवाला :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम को लगातार घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान औसतन कितनी धनराशि का घाटा हुआ है;

(ग) इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) इन घाटों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 1991–92 से 1993–94 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय बीज निगम को प्रति वर्ष 5.91 करोड़ रु० की औसत हानि हुई।

(ग) हानि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) बीज के बिक्री मूल्य में संगत वृद्धि के बिना आदानों के मूल्यों और बीज उत्पादकों को भुगतान किए जाने वाले अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि;

(2) राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण –1 और चरण–2 के अन्तर्गत सृजित बुनियादी सुविधाओं का अल्प-प्रयोग ; और

(3) अधिक स्टाफ।

(घ) मैसर्स टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेस ने निगम के कार्य की समीक्षा की थी और निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए इसके सुदृढ़ और कमजोर क्षेत्रों को चिन्हित किया था। इस अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख मदों पर विशेष जोर दिया गया :—

(क) यह कि राष्ट्रीय बीज निगम अपने कार्यकलापों के अधिकतर क्षेत्रों में कार्यकुशल नहीं रहा और इस प्रकार इसे हानि हुई ; और

(ख) यह कि राष्ट्रीय बीज निगम में उनके कारोबार की तुलना में स्टाफ बहुत अधिक था।

निगम की कार्य कुशलता मे सुधार लाने के लिए कन्सलटैन्ट्स की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :;–

(क) वे अपना उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलाप बढ़ाएं ;

(ख) वे अपने विभिन्न उत्पादों में संशोधन करें ; और

(ग) संशोधित उत्पादन तथा विपणन संबंधी कार्यकलापों के समरूप स्टाफ स्तर का समायोजन करें।

कन्सलटैन्ट्स की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए निगम के प्रबंधकों द्वारा उपर्युक्त कदम उठाए गए हैं।

Confiscation of edible oil from NDDB

4068. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI SAMIR PADHAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gujarat State Government has confiscated edible oils worth Rs. 135 crores from the warehouses of National Dairy Development Board;

(b) whether it is also a fact that the NDDB was permitted to store only 7,700 MT of imported edible oil;

(c) whether it is a fact that such storing of oil had created artificial shortage in the market; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) The Government of Gujarat had seized 22,119 MT edible oils stock from the godowns of NDDB.

(b) No, Sir. The stock limits of imported edible vegetable palmolein oil had been exempted from the purview of storage control order 177 vide the Govt. Notification dated 27th May, 1994.

(c) and (d) Since NDDB is continuously selling oil in the market from its stocks, therefore the question of artifical shortage of edible oil does not arise.

एच०एफ०सी० और एफ०सी०आई० में उत्पादन क्षमता

4069. **श्री आस मौहम्मद** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदूरदर्शिता के कारण एच०एफ०सी० और एफ०सी०आई० में उत्पादन क्षमता कम हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ;

(ग) उर्वरकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और